लोकतंत्र की आत्मा है - संवाद

हरियाणा संवाद

पाक्षिक : 1- 15 अक्तूबर, 2023 www.haryanasamvad.gov.in अंक - 75

"

मन व बुद्धि की एकाग्रता सकारात्मक सोच पर निर्भर करती है।

: अज्ञात

नारी शक्ति वंदन 3

मनोहर सरकार में किसान हुए खुशहाल 5

अमृत वाटिका के लिए कलश यात्रा 8

उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक में सीएम मनोहर लाल बोले

साझा प्रगति के लिए आवश्यक एसवाईएल

विशेष प्रतिनिधि

अमृतसर में उत्तर क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक का आयोजन हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई बैठक में एसवाईएल नहर के जल बंटवारे पर मुख्य रूप से चर्चा हुई। बैठक में पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित, जम्मू एवं कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू व उत्तर भारतीय राज्यों के प्रतिनिधियों ने शिरकत की। अमित शाह ने जल बंटवारे पर सभी राज्यों से अनुरोध किया कि वे खुले मन से चर्चा करते हुए इसका जल्द समाधान निकालने का प्रयास करें।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्यों की साझा प्रगति के राज्यों के बीच सहयोगपूर्ण माहौल अति आवश्यक है। राज्यों को चहिए कि वे अपने संसाधनों को एकत्रित कर परस्पर ज्ञान साझा करें और सर्वोत्तम पद्धतियां अपनाते हुए परियोजनाओं को कुशलतापूर्वक एवं प्रभावी ढंग से निष्पादित करना सुनिश्चित करें, जिससे पूरे क्षेत्र का समग्र विकास हो सके।

पाकिस्तान जाने से रोकना होगा पानी

मनोहर लाल ने कहा कि एसवाईएल निर्माण न करने बारे पंजाब का पक्ष है कि पानी की उपलब्धता कम हो गई है। लेकिन एसवाईएल का निर्माण और पानी की उपलब्धता दो अलग-अलग मुद्दे हैं। इस मामले में भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि रावी, सतलुज और ब्यास के पानी का अधिशेष, बिना चैनल वाला पानी पाकिस्तान में चला जाता है। (पिछले 10 वर्षों में सतलुज के पानी का औसतन 1.68 एमएएफ और रावी-ब्यास के पानी का 0.58 एमए.एफ पाकिस्तान की तरफ गया है)। इस राष्ट्रीय अपव्यय के सदुपयोग लिए एसवाईएल ज़रूरी है।

उन्होंने कहा कि भाखड़ा बांध/नंगल बांध से हरियाणा के लिए केवल एक कैरियर चैनल यानी 61 कि.मी. लंबा नंगल हाइडल चैनल है। इसका निर्माण 1954 के दौरान हुआ था, जो वर्तमान में 68 वर्ष पुराना हो गया है। यदि एनएचसी के पुराना होने की स्थिति में कोई दुर्घटना होती है, तो पूरी प्रणाली रुक जाएगी और हरियाणा को पानी की आपूर्ति नहीं हो पाएगी। ऐसे समय में एसवाईएल वैकल्पिक चैनल का काम भी करेगी। इसलिए भी एसवाईएल का निर्माण अति आवश्यक है।

बीबीएमबी के मुद्दों पर चर्चा

मनोहर लाल ने भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड के मुद्दों पर विचार-विमर्श करते समय कहा कि धूलकोट बीबीएमबी सब-स्टेशन की स्थिति को भी ध्यान में रखना होगा, जो वर्तमान में मरम्मत के कार्यों के कार्यान्वयन में देरी से प्रभावित है। इस बिजलीघर का कामकाज न केवल बिजली उत्पादन के लिए बल्कि जल संसाधनों के उचित प्रबंधन के लिए भी महत्वपूर्ण है। भाखड़ा मेन लाइन के तटों को ऊंचा करने के बारे में भी चर्चा आवश्यक है, क्योंकि इसका सीधा प्रभाव जल प्रवाह और संसाधन आवंटन पर पड़ता है। उन्होंने कहा सभी राज्यों को हथिनीकुंड पर एक राष्ट्रीय परियोजना के रूप में बांध के प्रस्ताव पर विचार करना चाहिए।

भारत 2023 INDIA

पर्यावरण संरक्षण जरूरी

मुख्यमंत्री मनोहर लाल 'कार फ्री डे' के मौके पर करनाल में मोटर साइकिल चलाते हुए लोक निर्माण विभाग विश्राम गृह से करनाल एयरपोर्ट तक पहुंचे। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहर में ट्रैफिक को कम करने और भीड़-भाड़ को खत्म करने के लिए हम सब छोटे-छोटे प्रयास कर सकते हैं। आधुनिकता के इस दौर में विकास के साथ-साथ स्वच्छ वातावरण भी ज़रूरी है। इसके लिए पेड़-पौधे हमारे लिए बहुत लाभकारी हैं, यह हमें न केवल छाया व फल देते हैं, बल्कि बरसात लाने में भी सहायक होते हैं। जीवन के लिए पर्यावरण संरक्षण बहुत ज़रूरी है। मुख्यमंत्री ने कार मालिकों से आह्वान किया कि जहां तक हो सके वे कार की बजाय साइकिल या मोटर साइकिल पर भी अपने रोज़मर्रा के काम निपटाएं।

मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के 'WhatsApp चैनल' से जुड़ें।

'हरियाणा एक हरियाणवी एक' के संकल्प के साथ अपने पूरे हरियाणा परिवार से जुड़ने के उनके प्रयास को सफल बनाएं।

बेहतर चिकित्सा सुविधाओं की प्रतिबद्धता

स्वास्थ्य बजट 9,647 करोड़ रुपए, एमबीबीएस की सीटें हुई 2,125

प्रदेश के लोगों को बेहतर चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए मनोहर सरकार निरंतर कार्य कर रही है। इसके लिए न केवल ढांचागत विकास किया जा रहा है बल्कि संस्थानों में पर्याप्त स्टाफ उपलब्ध कराने के भी ठोस इंतजाम किये जा रहे हैं। स्वास्थ्य बजट बढ़ाकर 9,647 करोड़ रुपए किया गया है तथा एमबीबीएस की सीटों की संख्या बढ़ाकर 2,125 की गई है।

स्वास्थ्य बजट में अभूतपूर्व रूप से वृद्धि हुई है। जहां वर्ष 2014 में स्वास्थ्य क्षेत्र का बजट मात्र 2,800 करोड़ रुपए था, वहीं आज वर्ष 2024-25 में 9,647 करोड़ रुपये हो गया है।

वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान प्रदेश में मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज, होम्योपैथिक कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज आदि की संख्या में इजाफ़ा हुआ है। नागरिकों को चिकित्सा सेवाएं सहजता से उपलब्ध हों इसके लिए हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं। फिलहाल प्रदेश में मेडिकल कॉलेज की संख्या 15 हो गई है। इनमें से 9 मेडिकल कॉलेज मनोहर सरकार के कार्यकाल में खुले हैं।

मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ाई गई है, जिससे एमबीबीएस की सीटों में 3 गुणा वृद्धि हुई है। वर्ष 2014 में प्रदेश में एमबीबीएस सीटें केवल 700 थी, आज यह संख्या 2,185 हो गई है। इतना ही नहीं, पीजी की सीटें भी 289 से बढ़कर 851 हो गई हैं।

स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए कुटैल, करनाल में पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय का निर्माण किया जा रहा है। भिवानी, जींद, गुरुग्राम व नारनौल जिला में 5 मेडिकल कॉलेज स्थापित किये जा रहे हैं। इनके अलावा, जिला फरीदाबाद, पंचकूला, कैथल, कुरुक्षेत्र, सफीदों व रेवाड़ी में छह राजकीय नर्सिंग कॉलेज खोले जा रहे हैं। छायंसा, फरीदाबाद में बंद हुए गोल्ड फील्ड मेडिकल कॉलेज को सरकार के अधीन लेकर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से शुरू किया गया है।

कुरुक्षेत्र में श्रीकृष्णा आयुष विश्वविद्यालय खोला गया है। करनाल में नर्सिंग कॉलेज व फिजियोथैरेपी कॉलेज खोले गए हैं। पंचकूला में राष्ट्रीय आयुर्वेद योग एंव प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान की स्थापना की जा रही है। बाढ़सा, जिला झज्जर में राष्ट्रीय कैंसर संस्थान खोला गया है। माजरा, जिला रेवाड़ी में एम्स स्थापित किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विगत सप्ताह यमुनानगर के गांव पांजुपुर में श्री गुरु तेग बहादुर साहिब राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। लगभग 1,200 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस कॉलेज को लगभग 30 माह में पूरा करने के प्रयास रहेंगे।

संपादकीय

'सीएम विंडो' से 'जनसंवाद' तक

प्रदेश के दस जिलों में 'जनसंवाद' की चर्चा चौतरफ़ा हो रही है। इस कार्यक्रम के तीन मुख्य उद्देश्य हैं। मुख्यमंत्री पहले लोगों को 'जनसंवाद' की भूमिका व उद्देश्य के बारे में बताते हैं कि यह कार्यक्रम धरातल पर सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और लोगों से सीधे फीडबैक लेने के लिए शुरू किया गया है। मनोहर लाल का कथन है कि यह कार्यक्रम ऐसा नहीं है कि केवल मंच पर बैठे व्यक्ति अपनी बात कहकर चले जाएं, ये वास्तव में जन संवाद कार्यक्रम हैं, जहां आप लोग अपनी बात कहेंगे और मैं भी।

दूसरे चरण में मुख्यमंत्री लोगों से पूछते हैं कि पिछले नौ वर्षों में सरकार द्वारा किए गए अनेकों कार्यों में से कोई एक कार्य बताएं कि जो आप को सबसे ज्यादा पसंद हो। तीसरे व अंतिम चरण चुने हुए जनप्रतिनिधि सरपंच व पार्षदों के भविष्य की योजना के बारे में पूछते हैं।

इस पूरे कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री व उनकी टीम लोगों द्वारा लिखित प्रतिवेदनों को भी प्राप्त करती है और मुख्यमंत्री आश्वासन देते हैं कि प्रतिवेदनों के एक-एक वाक्य को पढ़ा जाएगा और आपको सूचित किया जाएगा कि किस स्तर पर शिकायत व मांग की कार्रवाई चल रही है।

भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्व. श्री अटल बिहारी वाजपेयी के सुशासन की अवधारणा को सत्ता का आधार मानकर मनोहर लाल ने आम नागरिक की पहुंच प्रदेश के मुखिया तक पहुंचने के लिए 25 दिसंबर, 2014 को एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए सीएम विंडो की शुरुआत की थी। इस विंडो के माध्यम से प्रदेश का कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायतों को सीधे मुख्यमंत्री तक पहुंचा सकता है और इन नौ सालों में लगभग 10 लाख शिकायतें सीधे मुख्यमंत्री तक पहुंची हैं, जिनमें से अधिकांश शिकायतों का समाधान किया जा चुका है।

पंडित दीन दयाल उपाध्याय के अंत्योदय दर्शन को ज़मीनी हकीकत पर उतारने के लिए मुख्यमंत्री ने सीएम विंडो के बाद लोगों की शिकायतें, मांगें व सुझाव लेने के लिए सीधे लोगों के बीच जाने की पहल शुरू की थी। इसके लिए मुख्यमंत्री ने 2 अप्रैल, 2023 को भिवानी जिले से अपने जनसंवाद कार्यक्रम की शुरुआत की और यह लगभग साढ़े पांच माह में जन संवाद कार्यक्रम आज जन-जन की आवाज़ बन चुका है। अब हर कोई चाहता है कि जन संवाद कार्यक्रम उनके शहर या गांव में हो, ताकि उन्हें सीधे मुख्यमंत्री से बात करने का अवसर मिल सके। मुख्यमंत्री ने 90 दिनों के जनसंवाद कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की है, जिसमें से लगभग 25 दिनों के कार्यक्रम पूरे हो चुके हैं।

- संपादकीय सलाहकार

अध्यापकों को मिले मनपसंद स्कूल

शिक्षकों के स्थानांतरण में आने वाली अड़चनों को दूर करने के लिए बनाई गई ऑनलाइन स्थानांतरण नीति बेहद कारगर सिद्ध हो रही है। शिक्षकों को अपने चुने हुए विकल्पों में से पसंदीदा स्थान मिल रहे हैं, जिससे वे संतुष्ट है जिससे पठन-पाठन का कार्य और अधिक कुशलता से हो रहा है। इसी कड़ी में अब सरकार द्वारा 2004 बैच के प्राइमरी टीचर्स (पीआरटी) की अंतर जिला स्थानांतरण प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है, जिसमें 92 प्रतिशत अध्यापकों को उनकी पहली पसंद का जिला मिला है।

राज्य में शिक्षा के स्तर को सुधारने व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए राज्य सरकार निरंतर बेहतर प्रयास कर रही है। इसी दिशा में मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार मौलिक शिक्षा निदेशालय ने 2004 बैच के प्राइमरी टीचर्स (पीआरटी) के लिए अंतर जिला स्थानांतरण अभियान शुरू किया था। इसमें विभिन्न जिलों से 324 पीआरटी ने स्वेच्छा से आवेदन किया था। इन 324 शिक्षकों को वरीयता अनुसार 21 जिलों का विकल्प भरने को कहा गया था। स्थानांतरण प्रक्रिया पूरी होने के बाद 92 प्रतिशत शिक्षकों को उनकी पहली पसंद का जिला, सात प्रतिशत शिक्षकों को दूसरी पसंद का जिला और एक प्रतिशत शिक्षकों ने पारदर्शी स्थानांतरण प्रक्रिया के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया है।

गौरतलब है कि पीआरटी स्थानांतरण में कुछ कानूनी अड़चनें भी आई। परंतु सरकार ने उनका समाधान निकालते हुए शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। विभाग ने 13 सितंबर, 2023 को 2004, 2008 और 2011 बैच के पीआरटी के लिए अंतर जिला स्थानांतरण, 2017 बैच के पीआरटी के लिए स्थायी जिला आवंटन और सभी श्रेणियों के शिक्षकों के सामान्य स्थानांतरण के लिए कार्यक्रम जारी किया था।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल के निर्देशानुसार मौलिक शिक्षा विभाग द्वारा 2008 के पीआरटी शिक्षकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया भी 22 सितंबर से शुरू कर दी जाएगी। पीआरटी अपने विकल्प भरने सहित 22 सितंबर से स्वेच्छा से आवेदन कर सकेंगे।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में शिक्षा के स्तर में वृद्धि हो और हर बच्चा श्रेष्ठ बने। यह तब होगा जब शिक्षक पूरे मन से बच्चों को पढ़ाएंगे। इसके लिए शिक्षकों की परेशानियों को दूर करना सरकार का कर्तव्य है। हरियाणा सरकार की ऑनलाइन शिक्षक स्थानांतरण नीति अन्य राज्यों द्वारा भी सराही जा रही है और वे इसका अनुसरण कर रहे हैं।

श्रमिकों के कल्याण को समर्पित मोदी जन्मदिन

यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना 73वां जन्म दिवस भगवान विश्वकर्मा को समर्पित किया। उन्होंने देश के कामगारों व श्रमिकों को आत्मनिर्भर बनाने हेतु 'प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना' सहित कई अन्य योजनाओं शुभारंभ किया। योजना के तहत पारंपरिक कार्य करने वाले शिल्पकारों व कारीगरों को प्रशिक्षण, ऋण सुविधा व अन्य सहायता प्राप्त हो सकेंगी।

हरियाणा में 25 प्रतिशत श्रमिक संगठित क्षेत्र में हैं और 75 प्रतिशत असंगठित क्षेत्र के हैं। राज्य सरकार असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के कल्याण के लिए भी लगातार काम कर रही है। प्रदेश में दो श्रम कल्याण बोर्ड बनाए गए हैं। इनके माध्यम से श्रमिकों को विभिन्न प्रकार के लाभ प्रदान किए जाते हैं।

पलवल में विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय में आयोजित राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भगवान श्री विश्वकर्मा जयंती तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर प्रदेश व देशवासियों को बधाई दी।

> देश के विकास में सबसे अधिक भूमिका श्रमिकों की है। श्रमिकों के बिना विकास कभी संभव नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान श्री विश्वकर्मा की जयंती पर श्रमिकों के लिए अनेक योजनाओं की शुरुआत कर सही मायने में 'श्रमेव जयते' को चरितार्थ किया है। 'प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना' शुरू करके प्रधानमंत्री ने कारीगरों, श्रमिकों के जीवन में एक नई आशा भर दी है।
>
> **मनोहर लाल, मुख्यमंत्री, हरियाणा**

श्रमिकों के कल्याणार्थ अनेक घोषणाएं

मनोहर लाल ने औद्योगिक श्रमिकों के बच्चों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति में अभूतपूर्व बढ़ोतरी करने की घोषणा की। वर्तमान में छात्रवृत्ति की राशि, जो 5,000 रुपए से शुरू होकर 16,000 रुपए तक दी जाती थी, वह अब 10,000 रुपए से शुरू होकर 21,000 रुपए तक दी जायेगी।

श्रमिकों की सेहत का ख्याल

मुख्यमंत्री ने श्रमिकों को साइकिल खरीदने हेतु राशि बढ़ाकर 5,000 रुपए, महिला श्रमिकों को सिलाई मशीन खरीदने हेतु 4,500 रुपए करने की घोषणा की। क्रॉनिक बीमारी होने पर श्रमिकों को स्वास्थ्यप्रद खान-पान हेतु 2,000 रुपए प्रतिमाह दिए जाएंगे। परिवार का पालन-पोषण करने के लिए काम की तलाश में श्रमिकों को एक नगर से दूसरे नगर जाना पड़ता है, इसलिए उनकी सुविधा हेतु पहले चरण में फरीदाबाद, गुरुग्राम, सोनीपत व यमुनानगर में प्रत्येक जिले में 500-500 फ्लैट उपलब्ध करवाये जायेंगे।

गुरु शिष्य कौशल सम्मान योजना

विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय की ओर से 'गुरू शिष्य कौशल सम्मान योजना' शुरू की जा रही है। इसका उद्देश्य अनौपचारिक क्षेत्र के 25,000 शिल्पकारों, कारीगरों और श्रमिकों जैसे प्लंबर, बढ़ई, राजमिस्त्री आदि की कौशल क्षमता को पहचानना, प्रमाणित करना और उन्हें दक्ष गुरु के रूप में पहचान दिलवाना है। योजना का कुल बजट अनुमान 208.66 करोड़ रुपए होगा।

नए सफाई कर्मचारियों की भर्ती होगी:

सिरसा में आयोजित सफाईकर्मी सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत मिशन अभियान को सफल बनाने में सफाई कर्मियों का अहम योगदान है। सफाई कर्मी अपने बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान दे और उन्हें अच्छी शिक्षा देकर एक कामयाब इंसान बनाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब तक ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 10 हजार सफाई कर्मचारी कार्यरत हैं, जल्द ही एक हजार नए सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी।

बेटियों को इलेक्ट्रिक स्कूटी :

राष्ट्रीय श्रमिक दिवस राज्य स्तरीय समारोह में हरियाणा भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिकों की स्नातक कक्षा की पढ़ाई कर रही प्रदेश भर की 11 बेटियों को इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी की चाबी भी प्रदान की गई। जिनमें हिसार की पूजा, नूह की मीनाक्षी, महेंद्रगढ़ की चार बेटियों क्रमशः प्रियंका, नचिता, सोनम, सबिता को स्कूटी की चाबी भेंट की। इसके अलावा पलवल की प्रीति, हेमवती और कुसुम, आरती, चंद्रावती को इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी की चाबी प्रदान की गई।

पुरस्कार दिए गए:

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जिंदल अस्पताल के जितेंद्र सिंह को 'मुख्यमंत्री श्रम रत्न' और पानीपत के सतीश शर्मा को 'श्रम भूषण पुरस्कार' प्रदान किया, इसी प्रकार हरियाणा कौशल रोजगार निगम पंचकूला से दिलीप कुमार और फरीदाबाद के विरेंद्र सिंह को 'श्रमवीर पुरस्कार' तथा यमुनानगर की बबीता रानी और कमलेश रानी और शशिबाला को 'श्रम वीरांगना पुरस्कार' प्रदान किया। उन्होंने हरियाणा सुरक्षा, कल्याण एवं स्वास्थ्य पुरस्कार योजना के अंतर्गत भारी, मध्यम एवं लघु श्रेणी के कारखानों तथा निर्माण संस्थाओं के प्रतिनिधियों को पुरस्कृत किया गया।

सलाहकार संपादक : डा. चंद्र त्रिखा
सह संपादक : मनोज प्रभाकर
स्टाफ राइटर : संगीता शर्मा
संपादन सहायक : सुरेंद्र बांसल
चित्रांकन एवं डिज़ाइन : गुरप्रीत सिंह
डिजिटल सपोर्ट : विकास डांगी

राज्य सरकार ने अभिनेत्री मीता वशिष्ठ को हरियाणा फिल्म और मनोरंजन नीति के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए स्थापित गवर्निंग काउंसिल का अध्यक्ष नियुक्त किया है।

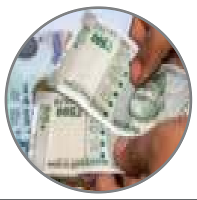

हरियाणा पहला ऐसा राज्य है जहां अब विधुरों को भी 40 साल की आयु के बाद 2,750 रुपए महीना पेंशन दी जा रही है। कुंवारों (45 से 60) को भी पेंशन देने का निर्णय लिया गया है।

नारी शक्ति वंदन

संगीता शर्मा

राजकाज में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने वाला 'नारी शक्ति वंदन विधेयक' लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी पारित हो गया। अब ये बिल विधानसभाओं में भेजा जाएगा। 50% विधानसभाओं से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। उनके हस्ताक्षर के बाद यह कानून बन जाएगा।

गौरतलब है कि 18 से 22 सितंबर तक बुलाए गए संसद के विशेष सत्र में इस बिल को पेश किया गया था। 20 सितंबर को लोकसभा में 7 घंटे की चर्चा के बाद यह बिल पास हुआ। इसके पक्ष में 454 और विरोध में 2 वोट पड़े। 21 सितंबर को बिल राज्यसभा में पेश हुआ। सदन में मौजूद सभी 214 सांसदों ने बिल का समर्थन किया और बिल पास हो गया।

विधेयक पारित होने के बाद हरियाणा की सैकड़ों महिलाएं नई दिल्ली हरियाणा भवन पहुंचीं। आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने भारत माता और 'मोदी है तो मुमकिन है' के नारे लगाए। महिलाएं इतनी प्रसन्नचित थीं कि ढोल-नगाड़ों पर नाचने लगी।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए नारी शक्ति वंदन विधेयक लेकर आने पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का धन्यवाद किया और सभी महिलाओं को इसके लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री मोदी जी के इस कदम की सराहना करता हूं कि लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा किया गया है। इससे राज-काज में बहनों की भागीदारी बढ़ेगी।

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने नारी शक्ति वंदन विधेयक के लिए महिलाओं को बधाई दी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने इसे संभव कर दिखाया है। उन्होंने नारी सशक्तिकरण के लिए प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई उज्ज्वला योजना, तीन तलाक से छुटकारा, हर घर नल से जल, जनधन योजना आदि का उल्लेख किया।

> कभी-कभी किसी निर्णय में देश का भाग्य बदलने की क्षमता होती है। हम ऐसे ही निर्णय के साक्षी बने हैं। जिस बात की देश को पिछले कई दशकों से प्रतीक्षा थी, वह सपना साकार हुआ है। नारी शक्ति वंदन विधेयक पारित होने से पूरे देश की महिलाओं का आत्मविश्वास आसमान छू रहा है। करोड़ों माताएं, बहनें, बेटियां ख़ुश हैं जिनका आशीर्वाद भाजपा कार्यकर्ताओं को नसीब हुआ है। यह कोई सामान्य कानून नहीं है। यह नए भारत का उद्घोष है।
>
> **नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री**

विधेयक में क्या है ख़ास

- विधेयक सीधे जनता द्वारा चुने जाने वाले प्रतिनिधियों पर ही लागू होगा। ये आरक्षण राज्यसभा या सभी छह विधान परिषदों पर लागू नहीं होगा। इस विधेयक में लोकसभा, राज्यों की विधानसभा और एनसीटी दिल्ली की विधानसभा शामिल है।
- विधेयक महिलाओं के लिए एक-तिहाई रिजर्वेशन डिलिमिटेशन यानी परिसीमन के बाद ही लागू होगा। विधेयक के कानून बनने के बाद जो पहली जनगणना होगी, उसके आधार पर परिसीमन होगा। आगामी पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा के चुनाव समय पर हुए तो इसमें महिला आरक्षण पारित होने के बावजूद लागू नहीं हो सकेगा।
- लोकसभा और विधानसभाओं में यह कानून जब लागू हो जाएगा, उसके बाद 15 साल तक अमल में रहेगा। उससे आगे रिजर्वेशन जारी रखने के लिए फिर से बिल लाना होगा और मौजूदा प्रक्रियाओं के तहत उसे पास कराना होगा। अगर 15 साल के बाद उस समय की सरकार नया बिल नहीं लाती है, तो ये कानून अपने आप खत्म हो जाएगा।

मोदी सरकार के विशेष कार्य

- पहले पांच साल के अंदर ही 11 करोड़ 72 लाख शौचालय बनाए।
- 10 करोड़ घरों में एलपीजी का मुफ़्त कनेक्शन दिया।
- 3 करोड़ से अधिक महिलाओं को उनके नाम से घर देने का काम किया।
- 80 करोड़ लोगों को प्रति व्यक्ति प्रतिमाह 5 किलो अनाज फ्री देने का काम किया।
- 3 करोड़ 18 लाख सुकन्या समृद्धि खाते खोले गए।
- 3 करोड़ महिलाओं को मातृ वंदन योजना के तहत फ़ायदा पहुंचाया
- 26 सप्ताह का मातृत्व अवकाश देने का काम किया।
- दुनियाभर में आज महिला पायलट्स की संख्या पांच प्रतिशत है जबकि भारत में 15 प्रतिशत।

हरियाणा में यह रहेगा प्रभाव

नारी शक्ति वंदन विधेयक का असर हरियाणा में भी दिखाई देगा। वर्तमान संख्या के आधार पर विधानसभा के लिए महिलाओं के लिए 30 और लोकसभा के लिए 3 सीटें आरक्षित होंगी। मगर वर्ष 2026 में नए सिरे से परिसीमन होगा, उसके बाद होने वाले चुनाव में यह आरक्षण व्यवस्था लागू हो जाएगी। हरियाणा में फिलहाल लोकसभा की 10 और विधानसभा की 90 सीटें हैं। अगर परिसीमन में आबादी के अनुसार लोकसभा की 3 सीटें बढ़ती हैं, तो कुल 13 सीटें हो जाएंगी जिनमें से चार लोकसभा सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। विधानसभा में सीटें बढ़कर 117 होने का अनुमान है तो 39 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी।

सशक्तिकरण के लिए पहल

महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ कदमताल मिलाकर आगे बढ़ रही हैं। 'नारी शक्ति वंदन विधेयक' से समाज में महिलाओं की स्थिति और बेहतर होगी। वे अपने और समाज के हितों के लिए देश की बड़ी पंचायतों में अपने हिस्से का हक प्रस्तुत कर सकेंगी। अधिनियम का हरियाणा में जोरदार स्वागत हुआ है। स्थानीय लोगों ने इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में अच्छा कदम बताया।

उल्लेखनीय है कि हरियाणा सरकार ने महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं में 50 प्रतिशत आरक्षण देकर महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम उठाया था। विगत नौ वर्षों में मनोहर सरकार ने महिला सशक्तिकरण व महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर विशेष बल दिया है।

महिला कल्याण के लिए 30 से अधिक योजनाएं

वर्तमान में, हरियाणा में महिलाओं के कल्याण की 39 योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनमें 31 हरियाणा सरकार की और आठ केंद्र सरकार की योजनाएं शामिल हैं। मुख्यमंत्री की पहल पर हर 20 किलोमीटर के दायरे में एक कॉलेज स्थापित किया गया है, परिणामस्वरूप अब लड़कियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए दूर नहीं जाना पड़ता। छात्राओं को परिवहन की सुविधा प्रदान करते हुए हरियाणा सरकार ने छात्रा सुरक्षित परिवहन योजना चलाई है, जिसके तहत स्कूल व कॉलेज तक लड़कियों के लिए 200 से अधिक विशेष बसें चलाई जा रही हैं। वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान 29 महिला आईटीआई स्थापित की गई हैं और आईटीआई में पढ़ने वाली लड़कियों को 500 रुपए प्रति माह वजीफा भी दिया जाता है।

स्वयं सहायता समूह

हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूह गठित कर महिलाएं अपने उत्पाद बेच कर आत्मनिर्भर बन रही हैं। प्रदेश में 56 हजार 434 महिला सहायता समूह हैं और इन समूहों को एक लाख रुपए से लेकर पांच लाख रुपए तक का ऋण एक प्रतिशत ब्याज दर पर उपलब्ध करवाया जाता है तथा स्टाम्प ड्यूटी में छूट दी जाती है।

महिला पुलिस की विशेष भर्ती

मनोहर सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा व महिला पुलिसकर्मियों के समक्ष खुलकर अपनी बात रख सकें इसके लिए महिला थाना खोलने की शुरुआत की थी। प्रदेश में 32 महिला थाने खोले गए हैं। हर पुलिस थाने में महिला हेल्प डेस्क स्थापित किया गया है। दुर्गा शक्ति ऐप, दुर्गा शक्ति वाहिनी सेवा, दुर्गा रैपिड एक्सन जैसी योजना लागू करने से महिलाओं में सुरक्षा की भावना जागृत हुई।

> प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं को चुनाव में 33 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए 'नारी शक्ति वंदन विधेयक' लेकर आये है, जो कि वर्षों से लंबित था। इसके अलावा मोदी जी ने 'वन नेशन-वन इलेक्शन' का नया विचार दिया है जो आने वाले समय में साकार होगा। पूरे समाज को साथ लेकर किस प्रकार से निर्णयों पर पहुंचा जा सकता है, यह मोदी जी ने सिखाया है।
>
> **मनोहर लाल, मुख्यमंत्री, हरियाणा**

गुरुग्राम की तहसील मानेसर के गांव कासन, कुकरोला और सहरावन में आई.एम.टी. मानेसर के विस्तार के लिए अधिग्रहित ज़मीन के मामले के समाधान हेतु नो-लिटिगेशन पॉलिसी बनाई है।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल पानीपत शहीद मेजर आशीष के आवास पर शोक व्यक्त करने पहुंचे। उन्होंने कहा कि परिवार को सरकार की तरफ़ से 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जायेगी।

रोगियों पर रहम करें, फसल अवशेष जलाना बंद करें

फसल अवशेष प्रबंधन के लिए जागरूकता अभियान

फसल अवशेष प्रबंधन के प्रति किसानों को ज़ागरूक करने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के तत्वावधान में ज़ागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट तथा केंद्र व प्रदेश सरकार के स्पष्ट निर्देश हैं कि कोई भी किसान फसलों के अवशेष न जलाएं। ऐसा करने से प्रदूषण बढ़ता है, जिसका दुष्प्रभाव लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ता है। विशेष रूप से श्वांस के रोगियों के लिए समस्या बढ़ जाती है।

फसल अवशेष प्रबंधन के लिए प्रदेश सरकार प्रति एकड़ की दर से 1,000 रुपए प्रोत्साहन राशि प्रदान कर रही है। सभी किसान संकल्प लें कि वे अपनी धरती मां की रक्षा के लिए पराली या धान के अवशेष नहीं जलाएंगे और उसका उचित प्रबंधन कर सरकार की इस योजना का फायदा उठाएंगे। किसान फसल अवशेष प्रबंधन से किसान पराली से कमाई भी कर सकते हैं। सरकार फसल प्रबंधन के लिए सब्सिडी पर कृषि यंत्र उपलब्ध करवा रही है, जिनकी सहायता से अवशेषों का प्रबंधन सरल हो जाता है। औद्योगिक इकाइयों में पराली का उपयोग होता है जो कि स्वयं इसकी खरीद करती हैं।

सभी किसान अवशेषों का प्रबंधन कर कृषि विभाग के पोर्टल agriharyana.gov.in पर 15 अक्टूबर तक अपना आवेदन अवश्य करें। किसान पराली न जलाएं इस पर नजर रखने के लिए टीम गठित की गई हैं। अगर कोई किसान धान के अवशेष या पराली जलाता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। किसानों से आह्वान किया जाता है वे फसलों के अवशेष किसी भी सूरत में न जलायें। प्रदूषण नियंत्रण में प्रशासन का सहयोग करें।

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उप-निदेशक डॉ. पवन शर्मा ने बताया कि पिछले वर्ष जिला में 60 प्रतिशत से ज़्यादा आगजनी की घटनाओं में कमी आई थी, आशा की जाती है कि इस बार कोई भी किसान पराली या धान अवशेष नहीं जलाएगा बल्कि कृषि यंत्रों के साथ उसका प्रबंधन करेगा। मोबाइल वैन चलाई गई हैं जो गांव-गांव जाकर लोगों को ज़ागरूक करेगी।

परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने फसल अवशेष प्रबंधन किसान ज़ागरूकता वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करते हुए लक्ष्य की प्राप्ति के लिए शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि मोबाइल वैनों के माध्यम से किसानों को गांव-गांव जाकर फसल अवशेष प्रबंधन के लिए ज़ागरूक किया जाएगा, ताकि कोई भी किसान अपनी धान के अवशेषों को जलाने की बजाए उसे कृषि मशीनों के माध्यम मिट्टी में ही मिला सके।

फूड प्रोडक्ट की गुणवत्ता से न हो कोई समझौता

वर्तमान दौर में अपने उत्पाद सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए डिजिटल मंच का अत्यधिक उपयोग करके एक सफल उद्यमी के तौर पर स्वयं को स्थापित कर सकते हैं। आज भारतीय इंडस्ट्री 4.0 के इस दौर में डिजिटल रिवोल्यूशन का चेहरा बना हुआ है। फूड प्रोसेसिंग में भी इसका कारगर उपयोग हो रहा है। विशेषकर उत्पादों को बेचने में डिजिटल प्लेटफार्म बहुत उपयोगी साबित हो रहे हैं। ज़्यादातर उपभोक्ता कोई भी खाने-पीने की चीज़ खरीदने के समय उसकी ऑनलाइन उपलब्धता तलाश करते हैं। इसलिए फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से जुड़े सभी लोग भी डिजिटल मंच का उपयोग कर अपने उत्पाद सीधे ही उपभोक्ताओं को बेच सकते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल सिरसा से सीएम की विशेष चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत ऑडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लाभार्थियों से सीधा संवाद कर रहे थे।

उच्च कोटि के पदार्थों की मांगः देश में वर्ष 2022 में फूड प्रोसेसिंग उद्योग 26 लाख करोड़ रुपए का था जो अगले तीन वर्षों में बढ़कर 35 लाख करोड़ रुपए तक होने की उम्मीद है। इसलिए इस उद्योग में निवेश व विकास की व्यापक संभावनाएं है। मनोहर लाल ने सभी उद्यमियों का कृषि प्रधान प्रदेश हरियाणा में फूड प्रोसेसिंग उद्योग को नए आयाम देने के लिए धन्यवाद भी व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से जुड़े लोगों ने उद्योग लगाकर न केवल हरियाणा के औद्योगिक क्षेत्र के विकास में, बल्कि रोज़गार बढ़ाने सहित लाखों किसानों की आय बढ़ाने में भी योगदान दिया है।

प्रदेश में 28 हजार फूड प्रोसेसिंग यूनिटः वर्तमान सरकार ने पिछले नौ सालों में प्रदेश में ऐसा माहौल बनाया है, जिसमें कारोबार करना आसान हो गया है, विभिन्न विभागों से अनुमति लेना सरल बना दिया गया है। हरियाणा कृषि व्यवसाय एवं खाद्य प्रसंस्करण नीति अधिसूचित करने के साथ-साथ, प्रदेश में फूड प्रोसेसिंग इकाइयों की स्थापना के लिए अनेकों प्रकार की सब्सिडी एवं करोड़ों रुपयों का सहायता अनुदान दिया जा रहा है। परिणामस्वरूप, हरियाणा में अब तक लगभग 28 हजार फूड प्रोसेसिंग यूनिट लग चुकी हैं।

एमएसएमई के लाभ उठाए उद्यमीः हरियाणा में उद्यम पंजीकरण पोर्टल पर 6 लाख 44 हजार 544 उद्यम पंजीकरण प्रमाणित एम.एस.एम.ई. हैं। इनमें से 27 हजार 370 एम.एस.एम.ई. पंजीकृत हैं। फूड प्रोसेसिंग इकाइयों के रूप में एम. एस.एम.ई. पॉलिसी व एचईईपी-2020 के तहत कुल 4,860 इकाइयों ने विभिन्न लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन किए हैं। इनमें से 1,501 इकाइयों को लाभ वितरित किए जा चुके हैं तथा 719 इकाइयों को लाभ देने की प्रक्रिया चल रही है।

उत्पादों की गुणवत्ता विश्व स्तर की होः फूड प्रोसेसिंग उत्पादों की गुणवत्ता विश्व स्तर के मानकों के अनुरूप होनी चाहिए ताकि हमारा उद्योग वैश्विक प्रतिस्पर्धा में टिक सके। ऐसे उत्पाद तैयार करें, जिनमें चीनी, नमक व फैट कम से कम हो, क्योंकि स्वास्थ्य के प्रति सचेत उपभोक्ता ऐसे खाद्य पदार्थों की मांग कर रहे हैं। पैकिंग आकर्षक और सुरक्षित होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार विदेशी सहयोग विभाग के माध्यम से प्रदेश की फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के उत्पादों की पहुंच अंतरराष्ट्रीय बाज़ार तक करने की योजना पर काम कर रही है ताकि उद्यमी अपने उत्पाद को विदेशों में भी बेच सकें।

जलापूर्ति के लिए ठोस पहल

मनोज प्रभाकर

'अटल भूजल योजना' के लिए गठित राज्य स्तरीय अंतर विभागीय संचालन समिति की बैठक में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 526.29 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन उपयोगिता योजना को मंजूरी दी गई है। यह योजना भूजल संबंधी समस्याओं को दूर करने और राज्य में स्थायी जल प्रबंधन को बढ़ावा देने की दिशा में कारगर साबित होगी।

हरियाणा सरकार इस पहल के माध्यम से राज्य में स्थायी और सुरक्षित जल भविष्य सुनिश्चित करने, जल संसाधनों का प्रबंधन करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने अधिकारियों से बड़े पैमाने पर सिंचाई और अन्य कार्यो में उपचारित अपशिष्ट जल के उपयोग को बढ़ावा देने के निर्देश दिए ताकि ट्यूबवेल के पानी का उपयोग कम हो सकें और जल संकट वाले ब्लॉकों में जल स्तर को गिरने से रोकने में मदद मिल सके।

अटल भूजल योजना के तहत क्रियान्वित की जा रही परियोजनाओं को तय समय सीमा में पूरा किया जाएगा। सभी तालाब परियोजनाओं को भी 31 मार्च, 2024 तक पूरा करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है।

समिति ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 307.98 करोड़ रुपए की वार्षिक कार्य योजना को भी मंजूरी दी। राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई हरियाणा द्वारा तैयार की गई इस योजना के संस्थागत सुदृढ़ीकरण और क्षमता निर्माण के लिए 82 करोड़ रुपए और प्रोत्साहन निधि उपयोग के लिए 225.98 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।

समिति ने जुलाई 2023 से जून 2024 की अवधि के लिए वार्षिक कार्य योजना को भी स्वीकृति दी। इन कार्य योजनाओं में आपूर्ति और मांग पक्ष गतिविधियों का अभिसरण, जल संरक्षण अपनाना और सूचना, शिक्षा, संचार और क्षमता निर्माण गतिविधियां, डाटा डिस्क्लोजर तथा जल सुरक्षा योजनाओं की तैयारी जैसे महत्वपूर्ण तत्व शामिल हैं।

विभिन्न परियोजनाओं पर कार्य जारी

हरियाणा में भूजल चुनौतियों से निपटने के लिए विभिन्न विभाग और संगठन प्रोत्साहन उपयोग योजना को लागू करने में सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं। सिंचाई और जल संसाधन विभाग द्वारा महेंद्रगढ़ के लिए आरसीसी पाइपलाइनों के निर्माण और संबंधित गतिविधियों के तहत नदियों और तालाबों के पुनर्भरण से भूजल बढ़ाने के लिए 27 परियोजनाएं शुरू की गई हैं। जिले की नौ परियोजनाओं का लक्ष्य भूजल की स्थिति में सुधार करना और भूजल को बढ़ाने के लिए विभिन्न गांव के तालाबों को पाइपलाइनों से जोड़ने के लिए तीन परियोजनाएं शुरू की गई है। जबकि 40 परियोजनाएं गांव के तालाबों को आरसीसी पाइपलाइन बिछाकर जोड़ने के लिए हैं। योजना में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के माध्यम से सिंचाई सुविधा प्रदान करने के लिए महेंद्रगढ़ में नौ नहरी जल भंडारण टैंकों का निर्माण भी शामिल है।

इसके अतिरिक्त कृत्रिम संरचनाओं के निर्माण से महेंद्रगढ़ जिले में भूजल स्तर में सुधार के लिए 16 परियोजनाएं संचालित की गई हैं। जिले में नांगल काठा से कुकसी तक कच्चा चैनल खोदकर, गांव खेड़की में तालाब की खुदाई करके और आरसीसी पाइपलाइन बिछाकर तथा कुकसी माइनर के अंतिम छोर को नदी से जोड़कर दोहान नदी को रिचार्ज करने के लिए भी एक व्यापक परियोजना तैयार की गई है।

फतेहाबाद जिले में भूजल की स्थिति में सुधार के लिए 40 रिचार्ज बोरवेल को मंजूरी दी गई है। हरियाणा पंचायती राज विभाग द्वारा अटल भूजल योजना के तहत यमुनानगर के गांव नवागांव और भोलीवाला में चेक बांधों को मज़बूत करने और मरम्मत करने का कार्य किया जा रहा है।

489 तालाबों का जीर्णोद्धार और कायाकल्प

हरियाणा तालाब और अपशिष्ट जल प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा वर्तमान में हरियाणा में अटल भूजल योजना के तहत 489 तालाबों के जीर्णोद्धार और कायाकल्प का कार्य किया जा रहा है। पलवल की विभिन्न ग्राम पंचायतों में 732 रूफटॉप रेनवाटर हार्वेस्टिंग संरचनाओं का निर्माण तथा सिरसा के ब्लॉक रानिया और ऐलनाबाद के गांवों के सरकारी भवनों में वर्षा जल संरक्षण के लिए 50 रिचार्ज बोरवेल का निर्माण तथा भूजल पुनर्भरण को बढ़ावा देने के लिए तालाबों का निर्माण भूजल योजना में शामिल है।

नालियां व चैक डैम

समिति द्वारा ग्राम पंचायतों में नालियां, चेक डैम, रिचार्ज शाफ्ट, छत पर वर्षा जल सरंक्षण और खेत तालाबों सहित 2,268 जल आपूर्ति संरचनाओं के निर्माण के लिए 40.75 करोड़ रुपए का आवंटित किये गये हैं। इन परियोजनाओं से किसानों की 101,214.5 हेक्टेयर भूमि की लेजर लैंड लेवलर्स में क्षमता निर्माण, शेड निर्माण और लेजर लैंड लेवलिंग तकनीक अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय, हिसार के मेला ग्राउंड में 8 से 10 अक्तूबर तक हरियाणा कृषि विकास मेले-2023 का आयोजन किया जाएगा।

डायल-112 आपातकालीन त्वरित सहायता प्रणाली पर 86 लाख से भी अधिक कॉल प्राप्त हुई हैं। यह सेवा प्रदेश के नागरिकों की सुरक्षा की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी।

मनोहर सरकार में किसान हुए खुशहाल

बीज से बिक्री तक किसानों के साथ खड़ी सरकार

विशेष प्रतिनिधि

मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सरकार के कार्यकाल में प्रदेश का किसान खुशहाल व समृद्ध हुआ है। राज्य सरकार किसानों को स्वाभिमानी बनाने तथा कृषि को जोखिम-मुक्त व्यवसाय बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। पिछले नौ सालों में सरकार ने कृषि क्षेत्र को लाभदायक सेक्टर बनाने और किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए निरंतर नई-नई योजनाएं बनाई हैं, जिनके तहत किसानों को विभिन्न प्रकार की सब्सिडी और अनुदान राशि दी जा रही है। यही वजह है कि हरियाणा का किसान राज्य सरकार की नीतियों से संतुष्ट है।

किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए मनोहर लाल ने एक नई पहल शुरू करते हुए किसानों को उनकी फसल का पैसा सीधा देने की कवायद शुरू की और किसानों को 72 घंटे के भीतर उनकी फसलों का भुगतान सुनिश्चित किया। पिछले 6 सीजन से अब तक फसल खरीद के 76,000 करोड़ रुपए की अदायगी सीधे किसानों के खातों में की गई है।

एमएसपी पर 14 फसलों की खरीद: मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सबसे अधिक 14 फसलों की खरीद करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया है। इतना ही नहीं, देश में सर्वाधिक 372 रुपए प्रति क्विंटल गन्ने का भाव भी सरकार दे रही है। इसके अलावा, फसलों की ऑनलाइन बिक्री के लिए 81 मंडियों को ई नाम पोर्टल से जोड़ा है।

कृषि क्षेत्र में ई गवर्नेंस: राजकाज में आईटी का उपयोग कर आईटी गुरु माने जाने मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कृषि क्षेत्र में भी ई गवर्नेंस लाने का बीड़ा उठाया है। परिणामस्वरूप 'मेरी फसल - मेरा ब्यौरा' पोर्टल विकसित किया गया, जिस पर लगभग नौ लाख किसान पंजीकृत हैं। इसके माध्यम से किसान फसल बेचने के साथ-साथ खाद, बीज, ऋण और कृषि उपकरणों के लिए मिलने वाली आर्थिक सहायता का लाभ घर बैठे ही उठा रहे हैं।

फसल नुकसान का मुआवज़ा: कृषि एक जोखिम भरा व्यवसाय है। किसानों की भावनाओं को समझते हुए मुख्यमंत्री ने एक ओर नई पहल शुरू की और किसानों को स्वयं अपनी फसल के नुकसान की जानकारी देने की स्वतंत्रता प्रदान की। इसी दिशा में प्राकृतिक आपदा से फसल नुकसान की भरपाई के लिए 'ई-फसल क्षतिपूर्ति पोर्टल' शुरू किया, जिस पर किसान फसल ख़राबे की जानकारी दर्ज करता है।

किसानों को नकद लाभ: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को समृद्ध करने के लिए 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना' की शुरुआत की है। इसके तहत, तहत हरियाणा के 19 लाख 70 हजार किसानों के खातों में 13 किस्तों में 4,288 करोड़ रुपए डाले गए हैं। इसके अलावा, 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' के तहत 20 लाख से अधिक किसानों को 7,071 करोड़ रुपए बीमा क्लेम के रूप में दिए गए हैं।

किसानों के हित में प्राकृतिक आपदा से ख़राब फसलों के लिए मुआवज़ा राशि बढ़ाकर 15 हजार रुपए प्रति एकड़ की है। सरकार द्वारा किसानों को 3,928 करोड़ रुपए की मुआवज़ा राशि दी गई। इसके अलावा, 75 से 90 प्रतिशत अनुदान पर 56,343 सोलर पम्प लगाए गए हैं।

सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित : किसानों को परंपरागत फसलों के अलावा बागवानी फसलों की खेती के लिए प्रोत्साहित करने हेतु प्रदेश में 14 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए हैं। इसके अलावा, किसानों को जोखिम-फ्री बनाने के लिए वर्तमान राज्य सरकार ने एक अनूठी 'भावांतर भरपाई योजना' शुरू की है। इसके तहत 21 बागवानी फसलों के संरक्षित मूल्य निर्धारित किए गए हैं। खरीफ सीजन-2021 से बाजरे की उपज भी भावांतर भरपाई योजना में शामिल की गई है। बागवानी फसलों का मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के तहत 40 हजार रुपए प्रति एकड़ तक बीमा की सुविधा भी प्रदान की गई है। सरकार ने फल एवं सब्जियों की ग्रेडिंग, भंडारण व मार्केटिंग के लिए 746 किसान उत्पादक समूहों से 1 लाख किसानों को जोड़ा है। आम, अमरूद और सिट्रस फलों के बाग लगाने पर प्रति एकड़ 20 हजार रुपए सब्सिडी, फल एवं सब्जियों के शीत भंडारण के लिए कोल्ड स्टोर पर 35 प्रतिशत अनुदान तथा मशरूम की खेती के लिए 40 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है।

मंडियों के आधारभूत ढांचे का विकास: प्रदेश के किसान खुशनसीब हैं कि यहां मंडियों का आधारभूत ढांचा बेहद मज़बूत है, इसलिए उन्हें फसल बेचने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आती है। राज्य सरकार निरंतर मंडियों के ढांचागत विकास पर ध्यान दे रही है। इसी कड़ी में गन्नौर, सोनीपत में 7,000 करोड़ रुपए की लागत से अंतरराष्ट्रीय स्तर की हॉर्टिकल्चर मार्केट बनाई जा रही है। इसके अलावा, सोनीपत जिले के सेरसा में मसाला मंडी व गुरुग्राम में फूल मंडी निर्माणाधीन है। पिंजौर में अत्याधुनिक नई सेब, फल व सब्जी मंडी का कार्य पूर्ण हो गया है।

सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली पर सब्सिडी: सिंचाई प्रबंधन को सुदृढ़ करने के लिए सूक्ष्म सिंचाई पद्धतियों पर 85 प्रतिशत सब्सिडी दी जा रही है। साथ ही, भूमिगत पाइप लाइन स्कीम के तहत किसानों को 10,000 रुपए प्रति एकड़, अधिकतम 60,000 रुपए प्रति किसान अनुदान राशि दी जा रही है। इसके अलावा, 20 साल से अधिक पुराने रजबाहों को दोबारा पक्का करने का काम जारी है और अमृत सरोवर मिशन के तहत 618 अमृत सरोवर बनाये गए हैं और 1116 पर कार्य जारी है।

जल संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री ने 'मेरा पानी- मेरी विरासत' योजना शुरू की, इसके तहत, फसल विविधीकरण और जल संरक्षण के लिए के लिए किसानों को 7,000 रुपए प्रति एकड़ वित्तीय सहायता दी जा रही है।

पशुधन क्रेडिट कार्ड योजना: किसानों के साथ-साथ पशुपालकों को भी सशक्त व समृद्ध बनाने के प्रयासों के तहत सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज़ पर 'पशुधन क्रेडिट कार्ड' योजना शुरू की है। इसके तहत 1 लाख 57 हजार पशुपालक लाभान्वित हुए हैं। साथ ही, 'पंडित दीन दयाल उपाध्याय पशुधन सुरक्षा' योजना के अंतर्गत 8.43 लाख पशुओं का बीमा किया गया है। हरियाणा गौ सेवा आयोग के माध्यम से 3,435 पंजीकृत गौशालाओं को 60 करोड़ रुपए की राशि दी गई। डेयरी के लिए दुधारू पशुओं की खरीद करने हेतु बैंकों से ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा भी दी गई है।

राज्य सरकार द्वारा किसानों के हित में चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं से निश्चित तौर पर कृषि लागत में कमी आई है और उपज का अच्छा दाम मिलने से किसानों की आय में बढ़ोतरी हुई है।

गन्ना बिक्री के विशेष इंतज़ाम

मोबाइल पर संदेश मिले, तो ही जाएं मिल

राज्य की सभी सहकारी चीनी मिल नवंबर से गन्ने की पिराई का कार्य शुरू कर देंगी। इसके अलावा किसानों को बिक्री के लिए गन्ना लाने में ज़्यादा समय तक इंतजार न करना पड़े। इसके लिए सभी आवश्यक प्रबंध किए गए हैं। सहकारिता मंत्री डा. बनवारी लाल राज्य स्तरीय शुगर फेडरेशन सहकारी चीनी मिल के अधिकारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

किसानों के मोबाइल पर संदेश आएगा तभी वह गन्ना मिल में लेकर आएंगे। इसके साथ ही मिलों में किसानों के लिए आवश्यक सुविधाएं मुहैया करवाने की व्यवस्था की गई है। किसानों को गन्ने के भुगतान की राशि समय पर मिलें। इसके लिए सरकार ने पुख़्ता प्रबंध किए हैं। पिछले सीजन की गन्ने की सभी बकाया राशि का भुगतान कर दिया गया है।

चीनी मिलों में एथनॉल प्लांट: चीनी मिलों की क्षमता और चीनी उत्पादन बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। शाहाबाद की चीनी मिल में 100 करोड़ रुपए की लागत से एथनॉल प्लांट लगाया गया है। पानीपत में भी एथनॉल प्लांट लगाने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। महम व कैथल चीनी मिल में इथेनॉल प्लांट लगाने की क्षमता 2500 से 3000 टीडीसी करना प्रस्तावित है। राज्य की सभी सहकारी चीनी मिलों में कलस्टर बनाकर एथनॉल प्लांट लगाए जाएंगे ताकि चीनी मिलों को आर्थिक रूप से मज़बूत बनाया जा सके।

शुगर मिलों की आय बढ़ाना: सहकारिता मंत्री ने कहा कि कई मिलों में रिफाइंड चीनी, बकेटस, कॉम्पैक्ट बायोगैस आदि बनाने का कार्य किया जा रहा है। इनसे शुगर मिलों की आय बढ़ेगी। इसके अलावा चीनी मिलों में प्रेस मड व शक्कर बनाने की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि फसल विविधकरण की वज़ह से इस बार गन्ने की बिजाई 1,97,581 एकड़ भूमि पर की गई है जो पिछले साल की तुलना में 17 प्रतिशत कम हुई है। इस वर्ष 424 लाख क्विंटल गन्ने की पिराई का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

वीटा उत्पाद को बढ़ावा: डा.बनवारी लाल ने कहा कि इस वर्ष चीनी की बिक्री करने में पानीपत चीनी मिल प्रथम, रोहतक चीनी मिल दूसरे व करनाल चीनी मिल तीसरे स्थान पर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य स्तर पर चार अधिकारियों की कमेटी गठित की जाएगी जो बगास बिक्री का रेट निर्धारित करेगी। बगास के लिए चीनी मिलें आपसी सहयोग कर बिक्री करने का कार्य सुनिश्चित करेंगी। उन्होंने कहा कि नेफेड की ओर से कैथल में चीनी मिल की भूमि पर सीबीजी प्लांट लगाया जाना प्रस्तावित है। सहकारिता मंत्री ने कहा कि वीटा के उत्पाद घर-घर पहुंचाने के लिए वीटा बूथ देने की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। इसके साथ ही अन्य राज्यों में भी वीटा उत्पाद पहुंचाने के लिए डिस्ट्रीब्यूटरशिप बढ़ाई जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में सभी पैक्स को हार्डवेयर कंप्यूटराईज करने का कार्य पूरा कर लिया गया है। - संवाद ब्यूरो

कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान में सत्र 2024-25 से एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। आईटीईपी कोर्स चार वर्ष की अवधि का होगा।

हरियाणा देश का पहला राज्य है, जहां पर किसानों की एक-एक एकड़ की फसल का पोर्टल पर पंजीकरण किया गया है। पोर्टल पर 99 फीसदी से ज़्यादा कृषि भूमि का पंजीकरण पूरा हो चुका है।

प्रगति के पथ पर हरियाणा रोडवेज

ई-टिक्टिंग के बाद अब एनसीएमसी कार्ड योजना

हरियाणा राज्य परिवहन ई-टिक्टिंग की सफलता के बाद नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी) सेवा शुरू करने जा रहा है। इससे परिवहन की बसों में रियायती दरों पर यात्रा करने वाले यात्रियों का पूरा डाटा कार्ड में होगा।

नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड द्वारा रियायती परिवहन सुविधाएं प्राप्त करने वाले व्यक्ति का पूरा कार्ड डाटा में शामिल होगा जो लोग हरियाणा परिवहन की बसों में रियायती सुविधाएं प्राप्त कर रहे हैं जैसे विद्यार्थी, 100 प्रतिशत विकलांग एक सहायक सहित, मान्यता प्राप्त संवाददाता, विधानसभा व लोक सभा के सदस्य, स्वतंत्रता सेनानी, पुलिस व जेल कर्मचारी, को केवल कार्ड दिखाना होगा। यदि किसी व्यक्ति के किराये में 50 प्रतिशत तक की छूट दी गई है तो उसका 50 प्रतिशत किराया नकद व एनसीएमसी कार्ड के माध्यम से भी दे सकता है। इस कार्ड को रीचार्ज करवाने की सुविधा भी परिवहन विभाग द्वारा दी गई है।

रोडवेज में ओपन लूप टिक्टिंग प्रणाली लागू करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। इस समय हरियाणा परिवहन की बसों में 2,317 मशीनों के माध्यम से ई-टिक्टिंग की जा रही है जिससे विभाग का लगभग तीन महीने में 17 करोड़ रुपए का राजस्व बढ़ा है।

प्रतिदिन लगभग 8 लाख यात्री

रोडवेज के पास इस समय कुल 3,723 बसें हैं जिनमें से 562 बसें निजी बस मालिकों से बस किराए पर चलाई जा रही हैं। प्रतिदिन यात्रियों की संख्या में वृद्धि हुई है। प्रतिदिन लगभग 8 लाख 6 हजार यात्री यात्रा करते हैं तथा बसें प्रतिदिन औसतन 10 लाख 77 हजार किलोमीटर की दूरी तय करती हैं।

विभाग के बेड़े में शामिल हुई नई बसें: वर्ष 2022 में विभाग द्वारा 1000 नई यूरो-6 बसें खरीदने हेतु ऑर्डर जारी किया गया था। वर्तमान में, इनमें से 745 बसें विभिन्न डिपों में भेजी जा चुकी हैं। विभाग के स्वीकृत बेड़े के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए नई बसें शामिल की जा रही हैं। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए 809 नई बसें खरीदने हेतु प्रचेज आर्डर कर दिए गए हैं और इन बसों का वितरण एचआरईसी, गुरुग्राम से चैसिस बस बॉडी लगने पश्चात विभिन्न डिपुओं में किया जा रहा है। वर्तमान में, 477 बसें विभिन्न डिपुओं को भेजी जा चुकी हैं। इसके अतिरिक्त, 153 एचवीएसी बसों की खरीद हेतु पर्चेज आर्डर किए जा चुके हैं जिसमें से 20 बसें संबंधित डिपुओं को प्राप्त हो चुकी हैं।

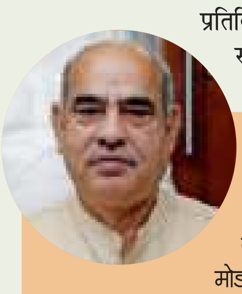

सुरक्षा की दृष्टि से बस अड्डों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। केंद्र सरकार की श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन योजना के तहत नवनिर्मित बस स्टैंड पानीपत में आरओ वाटर, वेंडिंग एटीएम लगाए जा रहे हैं ऐसा ही एक वाटर एटीएम पुराने बस स्टैंड पानीपत में पीपीपी मोड के तहत लगाया जा रहा है।

-मूलचंद शर्मा, परिवहन मंत्री

जानकारी के मुताबिक 12 मीटर स्टैंडर्ड फ्लोर एसी इलेक्ट्रिक बसें 375 ई-बसों की खरीद के प्रस्ताव को उच्चाधिकार प्राप्त ' य समिति की बैठक में स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इन बसों का संचालन नौ शहरों क्रमशः करनाल, सोनीपत, अंबाला, यमुनानगर, पानीपत, हिसार, रोहतक, पंचकूला और रेवाड़ी में किया जाएगा।

125 आधुनिक बस अड्डे व क्यू स्टेशन

हरियाणा राज्य परिवहन द्वारा यात्रियों की सुविधा के लिए राज्य में 125 आधुनिक बस अड्डे तथा बड़ी संख्या में बस क्यू शैल्टरों का निर्माण किया गया है।

विभाग द्वारा खेड़ी चोपटा (हिसार), झोझू कलां (चरखी दादरी), कादमा (भिवानी) में नए बस स्टैंड और कुरुक्षेत्र, बहादुरगढ़, महेंद्रगढ़, पलवल और कोसली (रेवाड़ी) में नई कार्यशालाओं का निर्माण किया जा रहा है।

विभाग द्वारा पीपीपी मोड पर एनआईटी फरीदाबाद बस टर्मिनल का विकास किया गया है जिसके बस टर्मिनल के निर्माण के लिए और सह-वाणिज्य सुविधाओं के विकास के लिए बोलियां आमंत्रित करने के बाद निजी भागीदार का चयन किया गया था। पीपीपी मोड के तहत गुरुग्राम, करनाल, पिपली, सोनीपत और बल्लभगढ़ में नए बस स्टैंडस के निर्माण भी प्रस्तावित है।

यात्रियों की सुविधा के लिए बस ठहराव के छोटे स्थानों पर बस क्यू शेल्टर भी उपलब्ध करवाए गए हैं। बस अड्डे पर यात्रियों को बहुत सी आवश्यक सुविधाएं भी दी जा रही हैं जैसे कि यात्रियों को आवश्यक सूचना हेतु पूछताछ काउंटर, अग्रिम बुकिंग प्रणाली काउंटर, समय सारणी भी विशेष रूप से प्रदर्शित की गई है। इसके अलावा, पर्याप्त सीटों सहित प्रतीक्षा कक्ष, पीने का स्वच्छ पानी, पार्किंग की सुविधा, रात्रि ठहराव के लिए यात्री निवास और क्लॉक रूम उपलब्ध करवाए गए हैं।

सुशासन में उपयोगी परिवार पहचान पत्र

2001 और 2011 की जनगणना के मध्य डेटा देरी से जारी होने के मुद्दों पर मनोहर लाल ने कहा कि इस दिशा में हरियाणा ने एक उल्लेखनीय पहल की है, जिसकी बदौलत जनसांख्यिकीय डेटा एकत्र करने और उपयोग करने के तरीके को बदल दिया है। उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक में उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने परिवार पहचान पत्र नामक एक प्रगतिशील योजना शुरू की है। केवल आवधिक जनगणना डेटा पर निर्भर रहने के विपरीत, परिवार पहचान पत्र हमें वास्तविक समय में अद्यतन जनसांख्यिकीय डेटा प्रदान करता है। इस योजना के माध्यम से, हमने एक व्यापक डेटाबेस तैयार किया है, जिसमें राज्य के प्रत्येक परिवार का डाटा है। इस डेटाबेस में व्यक्तियों और परिवारों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी शामिल है। यह हमारी सरकार के लिए योजना बनाने और नीति कार्यान्वयन के लिए एक मूल्यवान संसाधन है।

उन्होंने कहा कि परिवार पहचान पत्र योजना इस बात का एक ज्वलंत उदाहरण है कि कैसे प्रौद्योगिकी और नवोन्मेषी शासन डेटा संग्रह और उसके व्यावहारिक अनुप्रयोग के बीच के अंतर को पाट सकता है।

चिरायु योजना महत्वपूर्ण योजना

मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार ने स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। 21 नवंबर 2022 को हमने चिरायु योजना के माध्यम से अंत्योदय परिवारों तक आयुष्मान भारत का विस्तार के शुभारंभ के साथ नागरिकों के लिए व्यापक स्वास्थ्य देखभाल कवरेज सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। यह पहल समाज के सबसे कमजोर वर्गों को आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार पांच लाख रुपए तक का लाभ प्रदान करती है। 20 सितंबर 2023 तक इस योजना के तहत कुल 56,89,986 कार्ड बनाए गए हैं, जिसमें एबी-पीएमजेएवाई और चिरायु दोनों पहलों को मिलाकर कुल 8 5,79,273 आयुष्मान कार्ड जारी किए गए हैं।

उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2023-24 के बजट भाषण में की गई घोषणा को पूरा करते हुए पीएमजेए-चिरायु योजना का लाभ 1.80 लाख रुपए से लेकर 3 लाख रुपए तक की सत्यापित वार्षिक आय वाले परिवारों को भी देना शुरू किया है। इस लाभ के लिए प्रति परिवार प्रतिवर्ष 1,500 रुपए के मामूली अंशदान करना होता है। 14 अगस्त, 2023 को इसकी शुरुआत के बाद से, कुल 12,236 परिवारों ने सफलतापूर्वक अपना नाममात्र अंशदान जमा कर दिया है, जिससे उनके लिए योजना के स्वास्थ्य देखभाल लाभों को प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। उन्होंने कहा कि राज्यभर में 789 अस्पताल सूचीबद्ध किए गए हैं। जिनमें 175 सार्वजनिक और 614 निजी अस्पताल शामिल हैं। 9 लाख 10 हजार 525 से अधिक दावे प्रस्तुत किए गए और कुल दावा राशि 1,016.38 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया गया।

-संवाद ब्यूरो

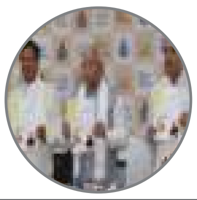

गरीब व ज़रूरतमंदों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने के दृष्टिगत 'मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना' बनाई गई है। इस योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को एक लाख मकान या प्लाट दिए जाएंगे।

अविकसित ब्लॉकों में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर सुधार लाने के उद्देश्य से 'ब्लॉक उत्थान कार्यक्रम' की शुरुआत के प्रथम चरण में अक्तूबर में 22 ब्लॉकों को कवर किया जाएगा।

हरियाणा के कालेजों को मिले पंजाब यूनिवर्सिटी से संबद्धता का विकल्प

उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंजाब विश्वविद्यालय में हरियाणा के कॉलेजों को संबद्धता देने संबंधी विषय पर बात करते हुए कहा कि छात्र हित में हरियाणा के कॉलेजों को पंजाब यूनिवर्सिटी से संबद्धता का विकल्प दिया जाना चाहिए।

उन्होंने बताया कि पंजाब विश्वविद्यालय में हरियाणा का हिस्सा पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 के तहत प्रदान किया गया था। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा 1 नवंबर, 1973 को एक अधिसूचना जारी कर इसे समाप्त कर दिया गया था। इससे पहले हरियाणा के तत्कालीन अम्बाला जिले के कॉलेज इस विश्वविद्यालय से संबद्ध थे। इसलिए अब हमारा यह मत है कि हरियाणा के तीन जिलों नामतः पंचकूला, अंबाला और यमुनानगर के कॉलेजों को पंजाब विश्वविद्यालय से संबद्धता दी जानी चाहिए। साथ ही, पंजाब के मोहाली और रोपड़ जिलों के कॉलेजों को भी पंजाब विश्वविद्यालय से संबद्धता दी जानी चाहिए। इसलिए बच्चों को शिक्षा का अवसर देना एक सकारात्मक सोच है।

उन्होंने कहा कि भारत की संस्कृति शिक्षा का प्रसार करने की रही है। एक समय दुनिया भर से लोग तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने आते थे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति शुरू की है। इसमें सब विश्वविद्यालय सर्वत्र शिक्षा प्रदान करने के लिए मुक्त हैं। फिर पंजाब विश्वविद्यालय को भौगोलिक सीमाओं में बांधकर क्यों रखा जाए। विश्वविद्यालय से जितने अधिक कॉलेज सम्बद्ध होंगे, इसकी उतनी ही अधिक ख्याति होगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय हरियाणा में अपना परिसर बना रहा है। इसके अलावा, राज्य में आई.आई.टी., दिल्ली का कैंपस भी बन रहा है। शिक्षा के विस्तार और कॉलेजों की संबद्धता से हरियाणा के साथ-साथ अन्य राज्यों के छात्रों को भी नए अवसर मिलेंगे।

-संवाद ब्यूरो

हरियाणा में निवेशकों के अनुकूल माहौल

मनोहर सरकार की औद्योगिक नीतियों का प्रभाव

विशेष प्रतिनिधि

हरियाणा में मनोहर सरकार की औद्योगिक नीतियों का डंका बज रहा है, परिणामस्वरूप देश-विदेश की कंपनियां राज्य में निवेश कर रही हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मानेसर में फ्लिपकार्ट के क्षेत्रीय वितरण केंद्र का शिलान्यास किया। साथ ही, वर्चुअल माध्यम से सोनीपत में किरयाना पूर्ति केंद्र का शुभारंभ किया। इन दोनों केन्द्रों से हरियाणा में निवेशकों की रूचि और बढ़ेगी। साथ ही युवाओं को रोज़गार के भी अधिक अवसर मिलेंगे। मानेसर में आयोजित शिलान्यास कार्यक्रम में उप-मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी विशिष्ट अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा के औद्योगिक एवं व्यापारिक क्षेत्र में दो नये मील पत्थर रखकर बड़े संतोष का अनुभव हो रहा है। हरियाणा में निवेशकों के लिए अत्यंत अनुकूल वातावरण है। उन्होंने बताया कि फ्लिपकार्ट द्वारा 285 एकड़ जमीन पर वेयरहाउसिंग और ट्रांसपोर्ट हब स्थापित किया जा रहा है। इसमें से 140 एकड़ जमीन पर 1,389 करोड़ रुपए के निवेश से बनाया जाने वाला यह क्षेत्रीय वितरण केंद्र एशिया का सबसे बड़ा वितरण केंद्र होगा। इससे 10 हजार लोगों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से रोज़गार मिलेगा। इसी प्रकार, सोनीपत में फ्लिपकार्ट के नये किरयाना पूर्ति केंद्र के माध्यम से रोज़गार के लगभग 2,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अवसर पैदा होंगे। साथ ही क्षेत्र के हजारों स्थानीय विक्रेताओं, एम.एस.एम.ई. और किसानों की पूरे देश के बाज़ार तक पहुंच बन जाएगी।

ग्लोबल सिटी गुरुग्राम :

मुख्यमंत्री ने गुरुग्राम में विकसित होने वाले ग्लोबल सिटी को क्षेत्र के विकास में नया अध्याय बताया। एनपीआर और सीपीआर के बीच करीब एक हजार एकड़ भूमि पर विकसित होने वाले ग्लोबल सिटी के काम को भी तेज़ी से आगे बढ़ाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट में एक लाख करोड़ रुपए का निवेश आने की प्रबल संभावना है। जिससे न केवल एनसीआर, बल्कि पूरे राज्य में रोज़गार के लाखों अवसर पैदा होंगे। इससे इलाके की नई तस्वीर उभरेगी।

वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक हब :

मनोहर लाल ने कहा कि फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियों के सहयोग से हम अपने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित कर रहे हैं। इसी दिशा में गुरुग्राम में ग्लोबल स्मार्ट सिटी और मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम जैसी प्रारंभिक महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का कार्यान्वयन शुरू कर दिया गया है। नारनौल में 886 एकड़ क्षेत्र में एकीकृत मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स हब विकसित किया जा रहा है। इसकी लागत 700 मिलियन अमरीकी डॉलर होगी। इसे दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट के सहयोग से विकसित किया जा रहा है।

फ्लिपकार्ट में नौकरियां :

फ्लिपकार्ट समूह देश में बड़े आपूर्ति श्रृंखला नेटवर्कों में से एक बन गया है। यह समूह हर महीने 14 लाख से अधिक विक्रेताओं के 50 करोड़ ग्राहकों को सामान की डिलीवरी कर रहा है। हरियाणा में फ्लिपकार्ट ने 95 हजार से अधिक स्थानीय नौकरियां पैदा की हैं, स्वयं सहायता समूहों और महिला उद्यमियों को समर्थन दिया है और स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा दिया है। हरियाणा में फ्लिपकार्ट ने अपनी आपूर्ति श्रृंखला के माध्यम से हजारों विक्रेताओं की पहुंच बाजार तक सुनिश्चित की है। साथ ही उन्हें देशभर के लाखों ग्राहकों तक पहुंचने में सक्षम बनाया है।

आधुनिक तकनीक का नया अध्याय

उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि फ्लिपकार्ट के क्षेत्रीय वितरण केंद्र शुरू होने के साथ ही हरियाणा की धरती पर लॉजिस्टिक के क्षेत्र में मॉडर्न आधुनिक तकनीक का एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। चौटाला ने कहा कि ई कॉमर्स बाजार के बढ़ते स्वरूप के चलते लॉजिस्टिक क्षेत्र में दिन प्रतिदिन कुशल कार्यबल की मांग बढ़ रही है। ऐसे में बेहतर होगा कि फ्लिपकार्ट प्रबंधन आस-पास के ग्रामीण क्षेत्रों में हरियाणा सरकार द्वारा संचालित राजकीय औद्योगिक इकाइयों के साथ करार कर अपनी सुविधा व ज़रूरत की हिसाब से कुशल कार्यबल तैयार कर सकता है।

गांवों और शहरों के बीच तीन करम से अधिक चौड़ाई वाले रास्तों को पक्का किया जाएगा। इनके अलावा स्वीकृत 1,647 सड़कों में से 1,632 सड़कों के टेंडर हो चुके हैं और 1,378 सड़कों का काम आवंटित किया जा चुका है।

tiol 2023 AWARDS

सुधारवादी राज्य की श्रेणी में हरियाणा को प्रथम पुरस्कार हासिल हुआ है। TIOL अवार्ड 2023 में हरियाणा को गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है।

नशामुक्त हरियाणा

मुख्यमंत्री की अपील

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नागरिकों से अपील की है कि वे नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में प्रशासन का पूरा सहयोग करें। लोगों को इसके दुष्प्रभाव के बारे में बताएं। अगर कहीं गड़बड़ लगती है तो फोन नं 9050891508 पर डायल कर पुलिस को अवगत कराएं। सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा।

नशा कोई भी हो, बुरा होता है। मनोहर सरकार ने यूं तो हर प्रकार के नशे को ढीला करने का प्रयास किया है लेकिन मादक पदार्थों के नशे के खिलाफ़ बड़ा अभियान चलाया है। कारगर योजनाएं बनाई गई हैं तथा जन जागरण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। सख़्ती से निपटने के लिए नियम कानूनों को गंभीरता से लागू किया जा रहा है।

मनोहर सरकार का प्रयास है कि प्रदेश की युवा शक्ति किसी भी सूरत में अपने पथ से न भटके, उसका पूरा ध्यान रचनात्मक कार्यों में लगे जिससे सभी परिवार आत्मनिर्भर बनें और देश प्रदेश का चहुंमुखी विकास हो। गौरतलब है कि मनोहर सरकार की नीतियों की बदौलत प्रदेश का युवा वर्ग पठन पाठन में विशेष रूचि ले रहा है। इतना ही नहीं, खेलों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। कहना गलत न होगा हरियाणा के युवाओं को आज अंतरराष्ट्रीय स्तर पर डंका बज रहा है। यह माहौल और रचनात्मक हो इसके लिए राज्य सरकार ने जागरूकता अभियान चलाए हैं ताकि युवा नशे के जाल में न फंसें। जो युवा गलती कर बैठे हैं उनको वापस जीवन धारा में लाने के प्रयास किये जा रहे हैं। हाल ही में राज्य सरकार की ओर से पूरे प्रदेश में साइक्लोथॉन यात्रा निकाली गई जो काफी लोकप्रिय रही और उसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिले।

राज्य सरकार ने नशीली दवाओं की लत से निपटने के लिए कई उपाय किए हैं, जिनमें अंतर-राज्य ड्रग सचिवालय की स्थापना, नशा मुक्ति केंद्र खोलना और उपचार और परामर्श सुविधाओं को सुदृढ़ करना शामिल है।

नशामुक्त हरियाणा को लेकर चली यात्रा में 1978 किलोमीटर की यात्रा करनाल में पूरी की। इस साइक्लोथॉन यात्रा में कुल 1 लाख 15 हजार से अधिक प्रतिभागियों ने साइकिल चलाई। तीन साइक्लिस्ट सोनीपत के जयपाल 66 वर्ष, रोहतक के सहदेव सिंह 65 वर्ष और रोहतक से ही 64 वर्ष की कमलेश राणा ने पूरी यात्रा में सहयोग दिया। यात्रा में किसी न किसी रूप में लगभग 4 लाख लोग शामिल हुए।

मुख्यमंत्री ने करनाल में कहा कि जन जागरण अभियान 5 मई 2023 से शुरू हुआ और 5 मई 2024 तक किसी न किसी रूप में चलता रहेगा। इस यात्रा में एनजीओ, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, आईटीआई के विद्यार्थियों ने भाग लिया है। इसके अतिरिक्त धार्मिक संस्थानों, प्रशासन और सरकारी विभागों ने भी एकजुट होकर सहयोग किया है।

नशीली दवाओं की लत के खिलाफ लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, नशीली दवाओं की लत के खिलाफ़ लड़ाई में पूरे समाज को एकजुट होने की जरूरत है। सरकार रोकथाम, पुनर्वास और सख़्त प्रवर्तन उपायों पर ध्यान देने के लिए प्रतिबद्ध है।

मुख्यमंत्री ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी और बिक्री से निपटने के लिए हरियाणा पुलिस द्वारा उठाए गए सक्रिय कदमों पर भी प्रकाश डाला, जिसमें नशीली दवाओं के पीड़ितों और नशीली दवाओं के तस्करों पर राज्यव्यापी डेटा एकत्र करने के लिए 'प्रयास' नामक एक मोबाइल ऐप का विकास भी शामिल है। इसके अलावा, नशीली दवाओं के व्यापार से संबंधित आपराधिक गतिविधियों की निगरानी के लिए एक केंद्रीकृत राज्य डेटाबेस बनाने के लिए 'हॉक' नामक एक सॉफ्टवेयर बनाया गया है।

हुक्का परोसने पर प्रतिबंध

राज्य में होटल, रेस्तरां, बार और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में ग्राहकों को हुक्का परोसने पर व्यापक प्रतिबंध रहेगा। यह रोक ग्रामीण इलाकों में इस्तेमाल होने वाले परंपरागत हुक्के पर लागू नहीं होगी।

रजिस्ट्री के साथ साइकिल

साइकिल चलन को बढ़ावा देने और पर्यावरण-अनुकूल परिवहन को प्रोत्साहित करने के लिए सीएम ने घोषणा की कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और व्यक्तियों को आवास सुविधाएं प्रदान करने वाला कोई भी लाइसेंस प्राप्त बिल्डर संपत्ति रजिस्ट्री के साथ संपत्ति के मालिक को एक साइकिल उपहार में देगा।

अमृत वाटिका के लिए कलश यात्रा

मेरी माटी मेरा देश

आजादी के अमृत महोत्सव और अमृत बेला के अवसर पर भारत सरकार संस्कृति मंत्रालय द्वारा 'मेरी माटी-मेरा देश' अभियान चलाया जा रहा है। हरियाणा में अभियान का पहला चरण 15 अगस्त को पूरा हो चुका है। दूसरे चरण में अमृत कलश यात्रा के माध्यम से गांव-गांव से मिट्टी एकत्र करने का कार्य जारी है। अभियान के दौरान सभी गांव, कस्बों व स्थानीय निकाय क्षेत्र से मिट्टी एकत्र की जा रही है।

अमृत कलश यात्रा के लिए गांव राणा खेड़ी में प्रत्येक घर से मिट्टी व चावल एकत्रित किए गए।

अमृत कलशों में जुटाई जा रही इस पवित्र मिट्टी को नई दिल्ली में स्थापित की जाने वाली 'अमृत वाटिका' में अर्पित किया जाएगा।

नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर के इस कार्यक्रम में 7,297 खण्डों एवं 500 से अधिक नगरपालिका एवं नगर परिषदों के लगभग 75 हजार जनप्रतिनिधि भाग लेंगे। इस राष्ट्रीय कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पांच प्रण की शपथ दिलवाएंगे और अमृत वाटिका का लोकार्पण करेंगे।

मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव तथा सूचना, लोक संपर्क, भाषा तथा संस्कृति विभाग के महानिदेशक डॉ. अमित अग्रवाल ने कहा कि एक ओर जहां हरियाणा के किसान इस मिट्टी से अन्न पैदा करके करोड़ों लोगों का पेट भरने का काम कर रहे हैं, दूसरी ओर यहां के खिलाड़ी इसी मिट्टी में खेलते हुए देश व प्रदेश गौरव बढ़ा रहे हैं। इतना ही नहीं इस मिट्टी में जन्मे यहां के नौजवान अपनी मातृ भूमि की रक्षा करने में भी कोई मौका नहीं गंवाते हैं। ऐसी मिट्टी को कोटि-कोटि प्रणाम। कहा जा सकता है कि देश के निर्माण की गौरव गाथा में हरियाणा की मिट्टी का विशेष योगदान है, जो समूचे प्रदेश के लिए गौरव का विषय है।

डॉ अमित अग्रवाल, भा.प्र.से. प्रबंध निदेशक, संवाद (सूचना जन संपर्क एवं भाषा विभाग) हरियाणा द्वारा हरियाणा सरकार के लिए कमरा नं. 314, दूसरी मंजिल, लघु सचिवालय, सेक्टर-1, पंचकूला से प्रकाशित।
कार्यालय : संवाद सोसायटी एससीओ 23, पहली मंजिल, सेक्टर 7, चंडीगढ़ फोन : 0172-2723814, 2723812 email : editorsamvad@gmail.com